

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 03 अक्टूबर, 2008

विषय- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-2-2004 से संशोधित दरों पर विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाना !

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 515/एडमिन०ए०/यू०एच०सी० दिनांक 21 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार करते हुये मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में निम्नलिखित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश संख्या- 217/सात उ०न्या०-124/88 टी०सी० दिनांक 15-3-1989 द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ 3 में उल्लिखित अनुमन्य विशेष भत्ता की वर्तमान दरों को स्तम्भ 4 के अनुसार दिनांक 1-2-2004 से संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारियों/कर्मचारियों का पदनाम	विशेष भत्ता की वर्तमान मासिक दर (रु०)	दिनांक 1-2-2004 से विशेष भत्ता की पुनरीक्षित मासिक दर (रु०)
1	मा० उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी तथा इसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी (दिनांक 1-1-1996 के पूर्व वेतनमान रु० 2000-3500 के अधिकारी)	140.00	280.00

✓

क्र० सं०	अधिकारियों/कर्मचारियों का पदनाम	विशेष भत्ता की वर्तमान मासिक दर (रु०)	दिनांक 1-2-2004 से विशेष भत्ता की पुनरीक्षित मासिक दर (रु०)
2	मा० उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी के वेतनमान (दिनांक 1-1-1996 के पूर्व वेतनमान रु० 2000-3500 से निम्न परन्तु समीक्षा अधिकारी के वेतनमान से उच्च वेतनमान वाले अधिकारी/कर्मचारी)	100.00	200.00
3	समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद	90.00	180.00
4	सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद (सहायक समीक्षा अधिकारी से उच्च किन्तु समीक्षा अधिकारी से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित होंगे)	60.00	120.00
5	टंकक/नैतिक लिपिक तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद (टंकक/नैतिक लिपिक से उच्च किन्तु सहायक समीक्षा अधिकारी से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित होंगे)	45.00	90.00
6	टंकक/नैतिक लिपिक से निम्न वेतनमान के पद	30.00	60.00

2. उक्त शासनादेश संख्या- 217(4)/सा-उ०न्या० दिनांक 15-3-1989 एवम् शासनादेश संख्या : 217/सात-उ०न्या०-124/88 टी०सी० दिनांक 15-3-1989 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

3. विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।



4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 999/xxvii(7)/2008 दिनांक 30 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव,

संख्या: 305/xxxvi(1)/(एक)2007-944/06 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 3- वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन ।
- 4- एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,